3 गीता निकेतन स्कूल में वार्षिक उत्सव

5 विवादों के बीच एक प्रभावशाली व्यक्तित्व

6 न्यूजीलैंड से कृषि उत्पाद निर्यात पर भारत की दृढ़ता

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 34 प्रति सोमवार, 29 दिसंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

निवेश के नाम पर आयोजन, ज़मीन पर सन्नाटा, यही है मध्यप्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट की हकीकत

करोड़ों खर्च, निवेश नदारद, क्या मध्यप्रदेश में विकास सिर्फ़ सम्मेलनों तक सिमट गया है?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर सरकार के दावे इन दिनों राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित रीजनल इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) और अब प्रस्तावित "एमपी ग्रोथ समिट" को लेकर एक ओर सरकार बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार और विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर आलोचक

इन आयोजनों की वास्तविक उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह आलेख इन्हीं सवालों, दावों और आशंकाओं का विश्लेषण करने का प्रयास है। सरकारी मंचों से यह बताया गया कि अब तक राज्य में 06 रीजनल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सरकार का तर्क है कि इन आयोजनों ने मध्यप्रदेश को निवेशकों के नक्शे पर मजबूती से स्थापित किया है। परंतु आलोचकों का कहना है कि निवेश प्रस्तावों और वास्तविक निवेश के बीच एक गहरी खाई दिखाई देती है। उनका दावा है कि आयोजनों पर लगभग 187 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि जमीन पर दिखाई देने वाला निवेश अभी तक बेहद सीमित है।

(शेष पेज 2 पर)

जल जीवन मिशन:

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सक्ती जिले में स्वच्छ पेयजल की मजबूत बुनियाद

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल जीवन मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। नवगठित सक्ती जिले में इस मिशन की प्रगति ने यह साबित किया है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जनभागीदारी और सतत निगरानी साथ-साथ चलें, तो बड़े लक्ष्य भी अपेक्षाकृत कम समय में हासिल किए जा सकते हैं। घर-घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में सक्ती जिला आज राज्य के अग्रणी जिलों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। जांजगीर-चांपा जिले से विभाजित होकर 9 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आए सक्ती जिले के सामने शुरुआत में बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई चुनौतियां थीं। जिला गठन के समय केवल 58 हजार 491 ग्रामीण परिवारों के पास ही घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध थे। ऐसे में जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देना शासन और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने इसे केवल आंकड़ों की योजना न मानते हुए ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने का माध्यम बनाया।

योजनाबद्ध क्रियान्वयन और ठोस निवेश

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सक्ती जिले के 456 गांवों के लिए कुल 565 जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं पर 601 करोड़ 72 लाख 72 हजार रुपये की लागत से कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं का लक्ष्य जिले के 1 लाख 56 हजार 245 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। (शेष पेज 7 पर)

विजयवर्गीय के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में दिखी अटल जी के संसदीय परंपरा की झलक

विधानसभा में दिया गरिमामय और ओजस्वी प्रेरक संबोधन

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में जब भी गंभीर, संतुलित और वैचारिक रूप से समृद्ध भाषणों की चर्चा होती है, तो नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम स्वतः ही सामने आता है। हाल ही में विधानसभा के विशेष सत्र में दिया गया उनका संबोधन केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और समावेशी सोच का जीवंत उदाहरण बन गया। इस संबोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति केवल विरोध या आरोप-प्रत्यारोप का मंच नहीं, बल्कि राष्ट्र और प्रदेश के विकास की साझा जिम्मेदारी का माध्यम भी हो सकती है। कैलाश विजयवर्गीय का भाषण इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि उसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की संसदीय परंपराओं और भाषाई सौम्यता की झलक स्पष्ट दिखाई दी। अटल जी जिस प्रकार तथ्य, भाव और राष्ट्रहित को एक सूत्र में पिरोकर अपनी बात रखते थे, उसी परंपरा को विजयवर्गीय ने अपने शब्दों में आगे बढ़ाया। उनका स्वर न तो कटु था और न ही उत्तेजित, बल्कि आत्मविश्वास से भरा, संतुलित और सभी पक्षों को साथ लेकर चलने वाला था।

(शेष पेज 2 पर)

कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में दिया गरिमामय और ओजस्वी प्रेरक संबोधन

(पेज 1 का शेष)

मुख्यमंत्रियों के उल्लेखनीय कार्यों का किया जिक्र

कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश के गठन के बाद से लेकर वर्तमान तक की विकास यात्रा का क्रमबद्ध और तथ्यात्मक उल्लेख किया। उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक के कार्यकाल में हुए उल्लेखनीय कार्यों को सामने रखा। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि वे इतिहास को किसी एक दल या सरकार की बपौती नहीं मानते, बल्कि उसे एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें हर सरकार का योगदान किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है। विजयवर्गीय ने जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों- जैसे शहरी अधोसंरचना, आवास योजनाएं, नगरीय सेवाओं का विस्तार और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का उल्लेख किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्षी सरकारों के सकारात्मक प्रयासों को भी स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। विशेष रूप से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पक्ष उल्लेख कर यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में प्रशंसा और आलोचना दोनों का स्थान है, बशर्ते वह तथ्य और सद्भावना पर आधारित हो।

भाषण में रखा निष्पक्षता का भाव

यह समानता और निष्पक्षता का भाव ही कैलाश विजयवर्गीय को एक परिपक्व और संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित करता है। आज के समय में, जब राजनीति अक्सर ध्रुवीकरण और कटुता की ओर बढ़ती दिखाई देती है, ऐसे में उनका यह दृष्टिकोण एक स्वस्थ परंपरा की पुनर्स्थापना करता है। विधानसभा जैसे पवित्र और गरिमामय मंच पर उन्होंने

निस्वार्थ भाव से अपनी बात रखी, जिसमें न तो व्यक्तिगत आरोप थे और न ही राजनीतिक विद्वेष। उनका उद्देश्य केवल प्रदेश की प्रगति और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सुदृढ़ करना प्रतीत हुआ।

अनुभवी और संवेदनशील नेता है कैलाश

विजयवर्गीय की राजनीतिक यात्रा भी उनके इस व्यक्तित्व को पुष्ट करती है। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और संगठन से लेकर सरकार तक विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। एक जनप्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान केवल उनके पदों से नहीं, बल्कि जनता से उनके जीवंत संवाद और संवेदनशील व्यवहार से बनी है। नगरीय निकाय एवं आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने शहरी विकास को मानवीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है।जहां आवास केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार है।

संवादप्रिय और संतुलित नेता

यह भी उल्लेखनीय है कि कैलाश विजयवर्गीय को पूर्व में कई बार विवादित बयानों से जोड़ने का प्रयास किया गया। किंतु यदि उनके सार्वजनिक जीवन और कार्यों को समग्रता में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि वे मूलतः एक संवेदनशील, संवादप्रिय और संतुलित नेता हैं। राजनीति में सक्रिय रहते हुए किसी भी नेता के वक्तव्यों को संदर्भ से अलग कर प्रस्तुत करना आसान होता है, लेकिन विजयवर्गीय ने अपने आचरण और कार्यों से बार-बार यह सिद्ध किया है कि उनकी मूल प्रवृत्ति सकारात्मक और रचनात्मक है। विधानसभा के विशेष सत्र में दिया गया उनका संबोधन विपक्षी दलों के लिए भी एक बड़ा संदेश था कि असहमति के बावजूद सम्मान बना रह सकता है और आलोचना के साथ-साथ सराहना भी की जा सकती है। यह संदेश केवल मध्यप्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी प्रासंगिक है। यदि सभी दल और नेता इस प्रकार की संसदीय परंपराओं को अपनाएं तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त, विश्वसनीय और जनोन्मुखी बन सकता है।

लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक

कैलाश विजयवर्गीय का यह भाषण इसलिए भी स्मरणीय रहेगा क्योंकि उसमें विकास की निरंतरता पर जोर दिया गया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन विकास की धारा को अविरल रहना चाहिए। इस सोच के साथ वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्रदेश के हित की बात करते नजर आए। यही कारण है कि उनके संबोधन को सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के कई सदस्यों ने भी गंभीरता से सुना और सराहा।

यह कह सकते हैं कि विजयवर्गीय का विधानसभा में दिया गया संबोधन भारतीय संसदीय लोकतंत्र की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां विचारों की भिन्नता के बावजूद संवाद की शालीनता बनी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी की संसदीय संस्कृति की झलक, इतिहास के प्रति सम्मान, वर्तमान के प्रति जिम्मेदारी और भविष्य के प्रति आशावाद-इन सभी तत्वों का सुंदर समन्वय उनके भाषण में दिखाई दिया। आज के राजनीतिक परिदृश्य में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो न केवल अपने दल का प्रतिनिधित्व करें, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक भी बनें। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने इस संबोधन से यह सिद्ध कर दिया है कि वे इस भूमिका को भली-भांति निभाने की क्षमता और इच्छाशक्ति रखते हैं। उनका यह प्रयास निश्चय ही मध्यप्रदेश की राजनीति को एक सकारात्मक दिशा देने वाला सिद्ध होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसदीय आचरण का एक प्रेरक उदाहरण बनेगा।

करोड़ों खर्च, निवेश नदारद, क्या मध्यप्रदेश में विकास सिर्फ़ सम्मेलनों तक सिमट गया है?

(पेज 1 का शेष)

संदेह पैदा होना स्वाभाविक है

यहीं से सवाल उठता है क्या निवेश प्रस्ताव और निवेश के बीच फर्क को जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखा जा रहा है? निवेश प्रस्ताव (एमओयू) अक्सर शुरुआती सहमति होते हैं, जिनका जमीन पर उतरना कई प्रक्रियाओं, अनुमतियों और व्यावसायिक निर्णयों पर निर्भर करता है। लेकिन जब लंबे समय तक बड़े-बड़े आयोजनों के बावजूद औद्योगिक इकाइयां, उत्पादन और रोजगार स्पष्ट रूप से न दिखें, तो संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) को लेकर भी ऐसे ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जीआईएस में करोड़ों रुपये खर्च हुए, देश-विदेश के प्रतिनिधि आए, मंच सजे, प्रस्तुतियां हुईं, लेकिन आम जनता के जीवन में उस निवेश का प्रत्यक्ष असर दिखाई नहीं देता। सवाल यह नहीं है कि आयोजन क्यों किए गए, बल्कि यह है कि इन आयोजनों से निकले वादों की निगरानी और क्रियान्वयन का तंत्र कितना प्रभावी है।

तर्क आंशिक रूप से सही भी है

सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि निवेश एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसके परिणाम रातों-रात नहीं दिखते। यह तर्क आंशिक रूप से सही भी है। परंतु आलोचक पूछते हैं कि यदि ऐसा है, तो फिर हर कुछ महीनों में नए नाम से निवेश सम्मेलन क्यों? "रीजनल इन्वेस्टर्स समिट", "ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट" के बाद अब "एमपी ग्रोथ समिट" क्या यह निरंतरता विकास की है या फिर आयोजन केंद्रित नीति का संकेत? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निवेश सम्मेलनों का एक प्रतीकात्मक महत्व भी होता है। वे राज्य की छवि गढ़ने, निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने और राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनते हैं। लेकिन जब प्रतीकात्मकता वास्तविकता पर भारी पड़ने लगे, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठना जरूरी हो जाता है। जनता का पैसा आखिर किन प्राथमिकताओं पर खर्च हो रहा है। यह प्रश्न किसी भी सरकार के लिए असहज नहीं, बल्कि आवश्यक होना चाहिए।

अनावश्यक आरोपों को भी स्वतः कमजोर कर देती है

आलोचकों द्वारा उठाया गया एक और गंभीर सवाल यह है कि क्या इन आयोजनों की स्वतंत्र ऑडिट और सार्वजनिक समीक्षा हो रही है? यदि वाकई निवेश प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा जमीन पर उतर चुका है या उतरने की प्रक्रिया में है, तो सरकार को आंकड़ों, परियोजनाओं की सूची और रोजगार के आंकड़ों के साथ सामने आना चाहिए। पारदर्शिता न केवल सरकार के पक्ष को मजबूत करती है, बल्कि अनावश्यक आरोपों को भी स्वतः कमजोर कर देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर सीधा आरोप लगाने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि निवेश नीति केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। यह पूरी शासन-प्रशासनिक मशीनरी, औद्योगिक विभाग, स्थानीय प्रशासन और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़ा विषय है। फिर भी, मुख्यमंत्री होने के नाते राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी अंततः उन्हीं पर आती है। यही कारण है कि सवालों की दिशा भी उन्हीं की ओर जाती है। "क्या यह सब जनता के टैक्स के पैसे से खेल है?" यह प्रश्न भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी। यदि जनता को लगे कि उनके पैसे का उपयोग केवल आयोजनों, मंचों और प्रचार तक सीमित है, तो असंतोष बढ़ना तय है। वहीं यदि सरकार ठोस उदाहरणों के साथ यह दिखा पाए कि निवेश के परिणामस्वरूप नए उद्योग, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास हो रहा है, तो यही सवाल प्रशंसा में बदल सकते हैं।

आलोचक इसे पुराने ढर्रे का विस्तार बता रहे

अब "एमपी ग्रोथ समिट" की घोषणा के साथ यह बहस और तेज हो गई है। समर्थक इसे नई ऊर्जा और नई दिशा का संकेत मान रहे हैं, जबकि आलोचक इसे पुराने ढर्रे का विस्तार बता रहे हैं। सच क्या है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि निवेश के नाम पर होने वाले हर आयोजन को अब केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि परिणामों से आंका जाएगा। अंततः लोकतंत्र में सबसे बड़ा निवेश जनता का भरोसा होता है। यदि यह भरोसा मजबूत रहा, तो नीतियां भी सफल होंगी। और यदि इसमें दरार आई, तो सबसे बड़े सम्मेलन भी उसे भर नहीं पाएंगे। इसलिए सवाल पूछना, जवाब मांगना और पारदर्शिता की अपेक्षा करना न तो विरोध है, न ही नकारात्मकता यह लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह इन सवालों का जवाब कैसे देती है आयोजनों से या उपलब्धियों से।

धार्मिक आस्था एवं देश की रक्षा के लिए सिख समाज का योगदान अतुलनीय : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाईटी द्वारा आयोजित वीरता सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 4 वीर साहसी बालकों को सम्मानित किया जिसमें साहिब फतेह सिंह वीरता पुरस्कार श्री प्रेमचन्द साहू,साहिबजादा जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार कु अंशिका साहू साहिबजादा जुझार सिंह वीरता पुरस्कार कु कांति सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह वीरता पुरस्कार श्री ओम उपाध्याय को प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा साहिबजादों का बलिदान हमेशा लोगो को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में धर्म, आस्था एवं देश की रक्षा के लिए सिख समाज का योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री साय ने कहा 26 दिसंबर को हम

वीर बाल दिवस मनाते हैं। आज के दिन हम दशम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने वीरता और गौरव की जो मिसाल दिखाई, वो अनुकरणीय है। इतनी छोटी आयु में भी वे किसी दबाव में नहीं आए, अपनी आस्था को नहीं छोड़ा, अपनी आस्था के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया। वह हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमें इस बात का गर्व है कि हम नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान के बारे में अवगत करा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। निश्चित रूप से इस पहल से बच्चों में शौर्य जगाने की जो अलख जगाई गई है वह सराहनीय कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने आयोजन के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी की प्रशंसा की एवं सभी साहसी बालकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को दुर्ग सांसद विजय बघेल एवं राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडेय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. कुलदीप सिंह सोलंकी ने स्वागत भाषण दिया एवं कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दीं। इस अवसर पर क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डॉयरेक्टर वरिष्ठ डॉ. संजीव दवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉ गिरीश चंदेल, आईएमए अध्यक्ष डॉ. नीरज शर्मा,डॉ वर्तिका मिश्रा, वरिष्ठ समाजसेवी अजय काले उपस्थित रहे।

स्कूल बच्चों की जान से खिलवाड़

प्राइवेट स्कूल की बसें बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के दौड़ रही सड़क पर, प्रबंधन बेख़बर, प्रशासन मौन

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, लेकिन नरसिंहपुर जिला अंतर्गत क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों में हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। यहाँ स्कूल प्रबंधन न सिर्फ अपने दायित्वों से दूर है बल्कि छात्रों की जान से भी खुला खिलवाड़ कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल में चल रही अधिकांश बसें फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन बीमा के बिना सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें रोजाना दर्जनों बच्चों का सफर करना किसी बड़े हादसे को निमंत्रण देने जैसा है।

बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे

स्कूल बसों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। यह इसलिए जरूरी होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन तकनीकी रूप से सुरक्षित है और सड़क पर चलने योग्य है। वहीं बीमा बच्चों और वाहन चालक, दोनों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा न होना एक बड़ी कानूनी और आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन नरसिंहपुर के इन निजी स्कूल में स्थिति बिल्कुल उलट है। बसें न तो समय पर फिटनेस कराई जा रही हैं और न ही बीमे का पालन किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई बसों की फिटनेस महीनों पहले समाप्त हो चुकी है। फिर भी वे लगातार बच्चों को स्कूल लाने–ले जाने में लगी हुई हैं। जब इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद लापरवाह रही। प्रबंधन की ओर से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि "हमें जानकारी नहीं है हम देखेंगे।" ऐसा लगता है जैसे बच्चों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। जबकि यह उनकी सीधी जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवहन संसाधनों को पूरी तरह नियमों के अनुरूप रखें।

साहिबजादों के वीरता एवं बलिदान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम राजधानी स्थित रेल्वे स्टेशन गुरुद्वारा पहुंचकर साहिबजादों की शहादत को नमन किया एवं मत्था टेका। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रथम गुरु गुरुनानक देव से लेकर 10वें गुरु तक सिख धर्म के सभी गुरुओं और उनके परिवारों ने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दीं। भारतीय इतिहास में सिख वीरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वीर बाल दिवस 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों की असाधारण वीरता और शहादत की याद दिलाता है। साहिबजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत पर हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। लगातार यह दिवस समारोह भव्यता एवं विराट रूप में मना रहे है। बहुत छोटी उम्र में साहिबजादों ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया और धर्म व सच्चाई की रक्षा के लिए महान साहस दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, हिम्मत और आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत हैं। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा सिख समाज की मांग पर हमारी सरकार साहिबजादों की बलिदान की गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हैं। कक्षा तीसरी की पाठ्यक्रम में इसे पढ़ाया जाएगा। निश्चित ही आने वाले पीढ़ियों को साहिबजादों के बलिदानों एवं साहस के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे देश के ऐसे वीर बलिदानों को इतिहास में स्वाभाविक स्थान नहीं मिला था जिसे हमारी सरकार वीर बाल दिवस की घोषणा कर उनकी वीरता एवं साहस को समाज के जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी,नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष सुरेन्दर सिंह छाबड़ा सहित सिख समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

नए साल में मिल सकता है बर्फबारी का तोहफा

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. नई दिल्ली। उत्तराखंड का मौसम नए साल में बारिश-बर्फबारी का तोहफा दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30-31 दिसंबर के साथ एक जनवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। उधर, 27 दिसंबर को दून समेत छह जिलों में शीत दिवस की स्थिति रहेगी। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में शनिवार को घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरा छाने से पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी सूखी ठंड परेशान करेगी। हालांकि 29 दिसंबर तक प्रदेशभर का मौसम शुष्क रहेगा। 30-31 दिसंबर और एक जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्सों में बारिश-बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके अलावा प्रदेश के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना है। इसका सीधा असर प्रदेश भर के तापमान में देखने को मिलेगा।

गीता निकेतन स्कूल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। स्थानीय गीता निकेतन को-एड स्कूल में 'तुलसी दिवस' के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरा अनुसार तुलसी पूजन एवं माँ सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सतीश शुक्ला, सुनील दुबे एवं ओ.पी. मुकाती उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मुक्त कंठ से सराहना की।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदेशों की रही धूम

वार्षिक उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न कलाकृतियों और नाटकों के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे:

सामाजिक नाटक: विद्यार्थियों ने 'नशा मुक्ति' और 'जल संरक्षण' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावशाली ड्रामा प्रस्तुत किया।

विविधता में एकता: भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक संस्कृति और लोक नृत्यों की सुंदर प्रस्तुति दी गई।

मॉडल प्रदर्शनी: विद्यालय में छात्रों द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक एवं रचनात्मक मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे अतिथियों ने खूब सराहा।

इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के डायरेक्टर गणेश पाटिल और श्रीमती निशा पाटिल का कुशल मार्गदर्शन रहा। साथ ही शिक्षिकाएं निर्मला कौशल, जेनू लोधंशी, पूजा अग्रवाल, वर्षा मालवीय, भावना कौशल, सिया परदेशी, योगिता मालाकार एवं ममता भार्गव मैडम का संपूर्ण और सराहनीय सहयोग रहा।

सम्पादकीय

भोपाल और मध्यप्रदेश में कटते पेड़ विकास के नाम पर हरियाली का संकट

मध्यप्रदेश को लंबे समय से "हरित राज्य" और "भारत का फेफड़ा" कहा जाता रहा है। घने वन, विस्तृत वन्यजीव क्षेत्र और प्राकृतिक विविधता इसकी पहचान रहे हैं। राजधानी भोपाल तो झीलों के साथ-साथ हरियाली के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध रही है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में, विशेषकर हाल के समय में, भोपाल और प्रदेश के अनेक हिस्सों में जिस तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, उसने इस पहचान को गहरे संकट में डाल दिया है। यह स्थिति केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुकी है।

सरकारें अक्सर पेड़ों की कटाई को "विकास" से जोड़कर सही ठहराने की कोशिश करती हैं। सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, स्मार्ट सिटी योजनाएँ, आवासीय कॉलोनियाँ और औद्योगिक विस्तार इन सभी के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। भोपाल में ही देखें तो केरवा, कलियासोत, लिंक रोड, बड़े पार्कों के आसपास और नए आवासीय क्षेत्रों में लगातार हरियाली कम होती जा रही है। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या विकास का कोई ऐसा मॉडल नहीं हो सकता जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चले? मध्यप्रदेश में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और विभिन्न वन नियम मौजूद हैं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले अनुमति, मुआवजा वृक्षारोपण और सार्वजनिक सुनवाई का प्रावधान भी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई बार अनुमतियाँ जल्दबाजी में दी जाती हैं और जनसुनवाई महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। वृक्षारोपण के नाम पर आंकड़े तो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, पर लगाए गए पौधों की देखरेख और उनके जीवित रहने की जिम्मेदारी तय नहीं होती। भोपाल कभी "ग्रीन सिटी" का उदाहरण माना जाता था। बड़े-बड़े पेड़, खुली जमीन और जैव विविधता इसकी पहचान थी। आज स्थिति यह है कि शहर के विस्तार के साथ-साथ पेड़ों का दायरा सिमटता जा रहा है। सड़क परियोजनाओं में पुराने और छायादार पेड़ों को हटाकर छोटे पौधे लगा देने को पर्यावरण संतुलन का विकल्प मान लिया गया है, जबकि एक परिपक्व पेड़ का पर्यावरणीय योगदान किसी नए पौधे से तुलना योग्य ही नहीं है। भोपाल और मध्यप्रदेश में कटते पेड़ केवल लकड़ी नहीं, बल्कि जीवन, संतुलन और भविष्य का नुकसान हैं। विकास यदि प्रकृति को खत्म करके होगा तो वह टिकाऊ नहीं हो सकता। आज आवश्यकता है कि सरकार, प्रशासन और नागरिक तीनों मिलकर यह तय करें कि विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री बनें। वरना आने वाले समय में यह हरियाली केवल तस्वीरों और यादों में ही रह जाएगी।

सियासी गहमागहमी

क्या ग्वालियर की राजनीति के मनमुटाव को साधने में सफल हुए शाह?

भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में संगठन और संतुलन साधना हमेशा से एक चुनौती रही है। हाल के घटनाक्रमों को देखें तो यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ज्योतिरादित्य सिंधिया, भरत सिंह कुशवाह और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे प्रभावशाली नेताओं को साधने में सफल हुए हैं, या यह संतुलन अभी भी प्रक्रिया में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका सरकार और संगठन दोनों में अहम है। उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी देकर भाजपा ने स्पष्ट संकेत दिया कि उनका कद पार्टी के लिए उपयोगी है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वे भाजपा के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमित शाह ने टकराव की बजाय समन्वय की नीति अपनाई है। हालांकि यह संतुलन स्थायी है या चुनावी जरूरतों तक सीमित, इसका असली जवाब आने वाले राजनीतिक फैसले और चुनावी नतीजे ही देंगे।

कमलनाथ के कार्यों की पार्टी आलाकमान में हुई सराहना

मध्यप्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का नाम आते ही किसानों से जुड़े फैसलों और नीतियों की चर्चा स्वतः शुरू हो जाती है। हाल ही में पार्टी आलाकमान द्वारा किसानों के हित में कमलनाथ के कार्यों की सराहना किया जाना इसी राजनीतिक पहचान को रेखांकित करता है। यह सराहना केवल एक औपचारिक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस रणनीति की स्वीकृति मानी जा रही है, जिसमें किसान को कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में रखने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने सबसे पहले किसानों के कर्जमाफी के मुद्दे को प्राथमिकता दी। भले ही इस योजना को लेकर राजनीतिक विवाद और प्रशासनिक चुनौतियाँ रही हों, लेकिन पार्टी नेतृत्व के नजरिए से यह कदम कांग्रेस की पारंपरिक किसान समर्थक छवि को मजबूत करने वाला था। इसके अलावा बिजली बिलों में राहत, समर्थन मूल्य को लेकर मुखरता और कृषि से जुड़े मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ स्पष्ट रुख ये सभी पहलें आलाकमान को यह संदेश देती हैं कि कमलनाथ जमीनी राजनीति को समझते हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?
क्या उसकी "गलती" ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है?
उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है - खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

"सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं।"

वीरता, साहस और बलिदान की प्रतिमूर्ति व सिख धर्म के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

दयानिधि मारन : राजनीति, संचार क्रांति और विवादों के बीच एक प्रभावशाली व्यक्तित्व

समता पाठक/जगत प्रवाह

दयानिधि मारन भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने अपेक्षाकृत कम आयु में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। वे न केवल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रमुख नेताओं में रहे हैं, बल्कि भारत के दूरसंचार क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों से भी उनका नाम जुड़ा रहा है। प्रशासनिक दक्षता, तेज निर्णय क्षमता और स्पष्ट राजनीतिक रुख के साथ-साथ विवादों ने भी उनके सार्वजनिक जीवन को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा। दयानिधि मारन का जन्म 5 दिसंबर 1966 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। वे एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता मुरासोली मारन, द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, वरिष्ठ पत्रकार और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मुरासोली मारन, डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि के भतीजे थे, इस प्रकार दयानिधि मारन का राजनीतिक और वैचारिक परिवेश बचपन से ही द्रविड़ विचारधारा से ओत-प्रोत रहा।

दयानिधि मारन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की। विदेश में शिक्षा के दौरान उन्हें वैश्विक राजनीति, संचार नीति और प्रशासनिक ढांचे को समझने का अवसर मिला, जिसका प्रभाव आगे चलकर उनके मंत्रीकाल में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने कुछ समय तक व्यवसाय और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में काम किया, लेकिन राजनीतिक विरासत और वैचारिक प्रतिबद्धता ने उन्हें सक्रिय राजनीति की ओर आकर्षित किया।

दयानिधि मारन ने वर्ष 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उसी वर्ष वे तमिलनाडु की चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। यह उनकी राजनीतिक क्षमता और पारिवारिक प्रभाव का संयुक्त परिणाम था, लेकिन संसद में उनकी सक्रिय भूमिका ने जल्द ही उन्हें एक स्वतंत्र पहचान दिलाई। उनकी तेज तर्रार शैली, तथ्यों पर पकड़ और मुखर वक्तृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में उभरते नेताओं की पंक्ति में खड़ा कर दिया।

वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के गठन के बाद दयानिधि मारन को केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। यह उनका राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दौर माना जाता है। दयानिधि मारन ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, निजी कंपनियों की भागीदारी और तकनीकी उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया। उनके कार्यकाल में भारत में मोबाइल फोन एक विलासिता से निकलकर आम आदमी की आवश्यकता बना। डीएमके में दयानिधि मारन को संगठनात्मक रणनीतिकार के रूप में भी देखा जाता रहा है। वे पार्टी की आधुनिक छवि, मीडिया प्रबंधन और राष्ट्रीय राजनीति में डीएमके की भूमिका को मजबूत करने के समर्थक रहे हैं। दयानिधि मारन का जीवन परिचय आधुनिक भारतीय राजनीति की जटिलताओं, उपलब्धियों और चुनौतियों का जीवंत उदाहरण है। वे संचार क्रांति के शिल्पकारों में गिने जाते हैं, तो वहीं विवादों और आलोचनाओं के कारण बहस का विषय भी बने रहे हैं। इसके बावजूद, भारतीय राजनीति और विशेषकर द्रविड़ आंदोलन के इतिहास में उनका स्थान एक प्रभावशाली और निर्णायक नेता के रूप में दर्ज है।

2026 की दहलीज:

यादों का बोझ उतारिए, संकल्पों को पंख दीजिए

नया साल तारीख नहीं, सोच बदलने का अवसर है

हर नया साल एक सवाल लेकर आता है—क्या बदलेगा? लेकिन असल सवाल यह होना चाहिए कि हम क्या बदलेंगे। कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं सोच, आदत और दृष्टि से। बीता हुआ साल अगर सिर्फ अफसोस, शिकायत और पछतावे के साथ विदा किया गया, तो नया साल भी वही कहानी दोहराएगा। 2026 की दहलीज पर खड़े होकर यह समझना जरूरी है कि बीते साल की असफलताएँ बोझ नहीं हैं, वे अनुभव हैं और अनुभव वही पूंजी है जिससे भविष्य की इमारत खड़ी होती है। नया साल उम्मीद का पोस्टर नहीं, आत्मसंयम और आत्मविश्वास की कार्ययोजना है।

बीते साल की विदाई: गलतियों को सबक में बदलने का समय

2025 ने हममें से कई लोगों को निराश किया होगा, किसी के सपने अधूरे रह गए, किसी को अपनों से ठेस मिली, तो किसी को अपने ही फैसलों पर पछतावा हुआ। लेकिन बीते साल को अगर हम केवल नुकसान की सूची मानकर याद रखें, तो हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। गलतियाँ जीवन का अंत नहीं होतीं, वे दिशा संकेत होती हैं। जो खो गया, उसे बार-बार याद करना मानसिक बोझ बढ़ाता है, लेकिन उस अनुभव से मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। पुरानी कड़वाहटों को नए साल तक ढोते रहना ऐसा है जैसे खाली बोतलें संभालकर रखना, उम्मीद करते हुए कि वे फिर भर जाएँगी। असफलताओं को खुद पर हावी करने के बजाय, उन्हें 2026 की सफलता की नींव बनाना ही समझदारी है।

जिन्होंने तोड़ना चाहा, उन्होंने मजबूत किया

जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आलोचना करते हैं, कमजोर आंकते हैं या जानबूझकर हतोत्साहित करते हैं। अक्सर हम उन्हें अपनी असफलता का कारण मान लेते हैं। जबकि सच यह है कि वही लोग हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। जिन्होंने हमें तोड़ना चाहा, उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें कितना मजबूत बनना है। विरोध और उपेक्षा अगर सही दृष्टि से देखी जाए, तो आत्ममंथन का अवसर बन जाती है। नए साल में सबसे जरूरी है - शिकायत नहीं, स्वीकार और सुधार।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

नए साल की शुरुआत: 'क्या होगा' से नहीं, 'मैं कर सकता हूँ' से

नया साल अक्सर डर के साथ शुरू होता है - क्या नौकरी सुरक्षित रहेगी, क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्या लक्ष्य पूरे होंगे? लेकिन डर के साथ शुरू किया गया साल कभी मजबूत नहीं बनता। 2026 की सही शुरुआत आत्मविश्वास से होनी चाहिए। नया साल तारीख बदलने का नाम नहीं, बल्कि खुद से किया गया वादा है। यह साल अपनी तुलना दूसरों से करने का नहीं, बल्कि खुद के बीते कल से आगे बढ़ने का है। बहानों की सूची छोटी करनी होगी और प्रयासों की संख्या बढ़ानी होगी। हर सुबह यह तय करना कि आज का दिन कल से बेहतर बनाना है यही नए साल का असली संकल्प है।

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य: सफलता की बुनियाद

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सबसे ज्यादा समझौता अपने स्वास्थ्य से करते हैं। जबकि सच यह है कि बिना स्वस्थ शरीर और शांत मन के कोई भी सफलता टिकाऊ नहीं होती। शुद्ध आहार केवल खान-पान का विषय नहीं, बल्कि आत्मअनुशासन का अभ्यास है। जंक फूड छोड़ना एक छोटा निर्णय लगता है, लेकिन यह बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। रोज कम से कम 30 मिनट शारीरिक श्रम न सिर्फ शरीर को फिट रखता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी चमकाता है। इसी तरह, दिखावे और शोर से दूर रहकर एकाग्रता और शांति को वापस पाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। किताबें, विचार और सीख - ये मन का पोषण करते हैं।

सफलता की तैयारी: आदतें बदलें, परिणाम बदलेंगे

हर बड़ा लक्ष्य छोटी आदतों से बनता है। बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उनकी नींव रोज के छोटे फैसलों से पड़ती है। समय की बर्बादी को अगर सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया जाए, तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। 2026 में मल्टीटास्किंग के भ्रम से बाहर निकलकर एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान देना जरूरी होगा। स्किल्स पर निवेश करना आज किसी विकल्प की तरह नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद को लगातार अपडेट रखता है। और सबसे अहम - मेहनत का शोर मचाने से बेहतर है, उसे शांति से जारी रखना।

जीवन का नजरिया: खुशी एक चुनाव है

अक्सर हम खुश होने के लिए किसी वजह का इंतजार करते हैं सफलता, पैसा या मान-सम्मान। जबकि सच यह है कि खुश रहना एक सचेत निर्णय है। दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना जीवन को गहराई देता है, क्योंकि देने का सुख पाने से कहीं बड़ा होता है। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करना जिन्हें बदला नहीं जा सकता, केवल मानसिक थकान बढ़ाता है। जीवन की समझदारी यही है कि जो हमारे नियंत्रण में है, उसी पर ध्यान दिया जाए।

2026: आपकी जिंदगी की अगली पटकथा

आखिरकार, हमारा भविष्य वैसा ही बनता है जैसा हम आज सोचते और जीते हैं। 2026 कोई जादुई साल नहीं, लेकिन यह वह साल हो सकता है जहाँ आप खुद की भूमिका बदल दें। यह साल आपकी जिंदगी की अगली फिल्म की पटकथा है और उसका हीरो कोई और नहीं, आप खुद हैं। फैसला आज करना है बीते साल को बोझ बनाकर ढोना है या 2026 को मजबूत आधार बनाकर आगे बढ़ना है।

न्यूज़ीलैंड से कृषि उत्पाद निर्यात पर भारत की दृढ़ता: दूध उत्पादक किसानों के सधे रहेंगे हित

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

विश्व कारोबार पटल पर भारत की महत्ता की स्वीकारता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में किसान हितों का पूरा ख्याल रखते हुए इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। याद रहे अमेरिकी कृषि उत्पाद निर्यात पर भारत ने दो टूक मना कर दी थी। इस कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजी का भारत ने बढ़ाए गए टैरिफ का सामना किया। इसकी भरपाई के लिए धैर्य से काम लेते हुए ब्रिटेन, ओमान और अब न्यूजीलैंड से अपनी शर्तों पर एफटीए करके किसान हितों को साधते हुए उल्लेखनीय समझौते कर लिए। इसी माह दिसंबर 2025 में भारत ने ओमान के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) किया था और अब भारत की न्यूजीलैंड से चली 9 माह की वार्ता में न्यूजीलैंड से इस बात पर सहमति हो गई कि इस समझौते में कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत से 5000 अभियंता न्यूजीलैंड काम करने के लिए जाते हैं। बावजूद यह समझौता शून्य टैरिफ पर होना भारत के दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा है।

इस समझौते से अमेरिका को इसलिए भी झटका लगा है, क्योंकि पांच साल पहले एशिया-प्रशांत व्यापार क्षेत्र के रूप में उभर रहे 15 देशों के व्यापार पटल आरईसीपी (रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) का सदस्य बनने से भारत ने इंकार कर दिया था। इसका मुख्य कारण था कि न्यूजीलैंड के सस्ते दूध और कृषि उत्पादों का भारत में निर्यात रोकना। अब भारत ने न्यूजीलैंड से स्वतंत्र रूप में समझौता करके किसान हितों को साध लिया है। दरअसल भारत में किसान और दुग्ध उत्पादक ग्वालों की प्रकृति पर निर्भरता होने के कारण आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। अतएव अमेरिका हो या न्यूजीलैंड यदि उनके सस्ते उत्पादों को भारत में बेचने की अनुमति मिल जाती है तो इन लोगों को रोटियों के लाले पड़ सकते है ? भारत इन उत्पादों की बजाय न्यूजीलैंड को सेब, कीवी, शहद और वाइन आयात करेगा। इनके आयात में टैरिफ में भी बड़ी राहत दी गई है। साथ ही न्यूजीलैंड सेब, कीवि और डेयरी क्षेत्र में भारतीय उत्पादकता को बढ़ाने में अपनी तकनीकि मदद भी देगा। अतएव यह समझौता पूर्ण रूप से भारतीय हितों को साधने वाला है।

वे भारतीय ऋषि ही थे, जिन्होंने सबसे पहले जाना था कि गाय के दूध में ऐसे पोशक तत्व हैं, जो शरीर और दिमाग दोनों को ही स्वस्थ रखते हैं। यह दूध ही है, जिससे दही, मठा, मक्खन और घी जैसे सह-उत्पाद निकलते हैं। ये उत्पाद मिठाई की दुकानों से लेकर डेयरी उद्योग के जरिए करोड़ों लोगों के रोजगार का मजबूत मध्ययम बने हुए हैं। लंबे समय तक गाय से पैदा बैल पर ही भारतीय कृषि निर्भर रही है। इसी कृषि की जीडीपी में 24 प्रतिशत की भागीदारी है। भारतीय दुग्ध उत्पादन से लेकर दूध पीने में दुनिया में पहले स्थान पर हैं। इसी दूध पर अमेरिकी बाजार के कब्जे के लिए अमेरिका अपने यहां उत्पादित मांसाहारी दूध बेचना चाहता है। अन्य यूरोपीय देशों की निगाह भी इस दूध के व्यापार पर टिकी रही है, जिनमें से एक न्यूजीलैंड भी रहा है। अमेरिका और भारत के बीच 500 बिलियन डॉलर के व्यापार समझौते की बात चली थी। इस समझौते की सूची में अमेरिकन मांसाहारी दूध के उत्पाद षामिल थे। भारत सरकार ने इस बाबत दो टूक कह दिया था कि अमेरिकी दुग्ध उत्पादों को भारतीय बाजार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। यह हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका और उनकी संस्कृति की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा प्रष्न है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। इस मनाही के बाद अमेरिका ने भारत पर अनर्गल टैरिफ संबंधी शर्तें थोपना शुरू कर दी थीं।

भारत में 13 जनवरी 1970 को फ्लड ऑपरेशन के साथ दूध का उत्पादन शुरू हुआ था। इसे ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। यह केवल भारत में ही नहीं विष्व में सबसे बड़े ग्रामीण कार्यक्रमों में से एक है। इसी की बदौलत भारतीय डेयरी उद्योग का चेहरा बदला और लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों की आर्थिकी में क्रांतिकारी बदलाव आया। दरअसल फिरंगी हुकूमत के दौरान पोल्सन नाम की ब्रिटिष कंपनी का इस क्षेत्र का दूध खरीदने पर एकाधिकार था। कंपनी दुग्ध उत्पादकों का लगातार शोषण कर रही थी। इस शोषण की शिकायत किसानों ने सरदार पटेल से की। पटेल गोधन, गोरस और गोदान की हिंदू जीवन शैली के अनुयायी थे। पटेल शोषण की जानकारी से बेचैन हुए और लौहपुरूष के अवतार में आ गए, उन्होंने तत्काल कंपनी को दूध बेचने से मना कर दिया। उनका मानना था कि जब कंपनी को दूध मिलेगा ही नहीं, तो उसे किसानों की शर्तें मानने को मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही पटेल ने सभी किसानों को मिलकर सहकारी संस्था बनाकर स्वयं दूध और दूध के उत्पाद बेचने की सलाह दी। पटेल के इस सुझाव से किसान सहमत हो गए और अंग्रेजों को दूध न देने की चुनौती दे दी। बाद में 1946 में पटेल ने अपने भरोसे के साथ ही मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास पटेल की सहायता से भारत की पहली दुग्ध सहकारी संस्था की स्थापना की, इसे ही बाद में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के नाम से जाना गया। 250 लीटर दूध का प्रतिदिन कारोबार करने वाली इसी संस्था को आज विश्वव्यापी संस्था 'अमूल' के नाम से जाना जाता है। मिषिगन स्टेट विवि से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भारत लौटे वर्गीज कुरियन ने सरकारी नौकरी छोड़कर इस संस्था में काम षुरू किया और भारत का पहला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया। इसके बाद किसानों की ज्ञान परंपरा और कुरियन के यांत्रिक गठबंधन से इस संस्था ने उपलब्धि का षिखर चूम लिया।

बिना किसी सरकारी मदद के बूते देश में दूध का 70 फीसदी कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। लेकिन पारंपरिक ज्ञान से न केवल वे बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन में सफल हैं, बल्कि इसके सह-उत्पाद दही, मठा, घी, मक्खन, पनीर, मावा आदि बनाने में भी मर्मज्ञ हैं। दूध का 30 फीसदी कारोबार संगठित ढांचा, मसलन डेयरियों के माध्यम से होता है। देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हैं। 14 राज्यों की अपनी दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं। देश में कुल कृषि खाद्य उत्पादों व दूध से जुड़ी प्रसंस्करण सुविधाएं महज दो फीसदी हैं, किंतु वह दूध ही है, जिसका सबसे ज्यादा प्रसंस्करण करके दही, मठा, घी, मक्खन, मावा, पनीर आदि बनाए जाते हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे आठ करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी है। करीब 1.5 करोड़ परिवार ही सहकारी दुग्ध उत्पादकता से जुड़े हैं, जबकि 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवार आज भी सहकारिता के दायरे से वंचित हैं। दूध उत्पादन में ग्रामीण महिलाओं की अहम् भूमिका रहती है। रोजाना दो लाख से भी अधिक गांवों से दूध एकत्रित करके डेयरियों में पहुंचाया जाता है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण सीधे षहरी एवं कस्बाई ग्राहकों तक भी दूध बेचने का काम करते हैं।

इसी दूध के बाजार पर अमेरिका समेत अनेक दुग्ध उत्पादक पष्चिमी देशों की निगाहें टिकी रहती हैं। हालांकि अब दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुछ माह पहले ही दस हजार नई कृषि सहकारी समितियों को हरी झंडी दिखाई है। अगले पांच साल में इनकी संख्या दो लाख तक पहुंचाने की है। इन्हीं सहकारी संस्थाओं के जरिए कृषि और दुग्ध उत्पादों को भारत से लेकर एषिया और यूरोप तक बाजार में पहुंचाने की तैयारी है। ऐसे में यदि अमेरिकी या अन्य देषों के लिए दुग्ध उत्पाद बेचने के लिए भारतीय बाजार खोल दिए जाते तो इन सम्मितियों की मुश्किलें तो बढ़ती हीं, दुग्ध उत्पादक आठ करोड़ लोगों की आजीविका पर भी संकट के बादल गहरा जाते।

नए साल में प्रकृति से जुड़े

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

नए साल का आगमन हम सभी के लिए नई उम्मीदें और नई योजनाएं लेकर आता है। यह समय होता है जब हम अपने जीवन में नई दिशा और सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस नए साल में, आइए हम सभी मिलकर प्रकृति से जुड़े और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। पर्यावरण संरक्षण का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना या प्लास्टिक का उपयोग कम करना नहीं है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें जल, वायु, भूमि, और सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है। नए साल में हमें छोटे-छोटे कदम उठाकर इस दिशा में अपना योगदान देना चाहिए।

पानी का संकट आज सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हम इससे पार पा सकते हैं। सरकार ने भी इस समस्या के प्रति अपनी गम्भीरता स्पष्ट कर दी है। ऐसे में अब बारी समाज की है। भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 140 लीटर है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक दिन में प्रति व्यक्ति को 200 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए। देश के 85- 90 प्रतिशत गांव भूजल से अपनी आपूर्ति करते हैं। पानी का संरक्षण व उसकी बचत दोनों स्तरों पर जल संकट के स्थाई समाधान हेतु जहां तालाबों का पुनर्जीवित होना आवश्यक है वहां अति आवश्यक है कि वर्षा के प्रत्येक बूंद का हम संचयन करें एवं अनुशासित हो कर जल के उपयोग के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। खुली हवा में सांस लेने के लिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें खुद इसके लिए जिम्मेदारी लेकर दूसरों को भी जागरुक करना होगा। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारकों में बढ़ते वाहन, आवासीय क्षेत्र व नजदीक में चल रहे उद्योग धंधे, खुले में पड़ी भवन निर्माण सामग्री, मानक के विपरीत चल रहे ईंट भट्टे, खुले में जलाए जा रहे प्लास्टिक-पॉलीथीन व कूड़ा है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी विभागों के साथ मिलजुलकर काम करने का संकल्प लेना जरुरी है। वायु की खराब गुणवत्ता का रिश्ता दिल की बीमारी, फेफड़े का कैंसर, दमा और सांस रोगों से है। पॉलीथीन और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के अंधाधुंध प्रयोग तीव्रता से पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। यह हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। गांव, कस्बों, और शहरों की इस्तेमाल किए गए सामानों से पटी पड़ी हैं जो मिट्टी में नही घुलता है और धीरे धीरे पानी में चला जाता है और कुछ दिनों के बाद विभिन्न तरीकों से यह समुद्र में चला जाता है जिससे समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है। पक्षियों से लेकर मछलियों और अन्य समुद्री जीवों तक हर साल प्लास्टिक से लाखों जानवर मारे जाते हैं। ज्ञात है कि लुप्त प्रायः प्रजातियां सहित और लगभग हर प्रजातियों सहित लगभग 700 प्रजातियां प्लास्टिक से प्रभावित है। हमें इस नए साल में यह संकल्प लेना होगा कि एकल प्रयोग प्लास्टिक की इस्तेमाल न खुद करेंगें और दूसरों को ऐसा करने से रोकेंगे।हमारे देश में पेड़ों की संख्या कम है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि लोगों के पास पौधारोपण करने का समय नहीं है। जब प्रदूषण जी का जंजाल बना हुआ है और शुद्ध हवा के लिए लोग तरस रहे हैं तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वे वृक्षारोपण को बढ़ावा दे ताकि भावी पीढ़ी को शुद्ध हवा नसीब हो सके। पेड़ों के तनों से कार्बन डायऑक्साइड सोखने की अद्भुत क्षमता है। हरियाली के अभाव मे यही कार्बन उत्सर्जन वायु मंडल में जाकर मौसम को गड़बड़ा रहा है। हम संकल्प लें कि धरती की हरियाली को कम नहीं होने देंगे। घरेलू कचरे को सही तरीके से अलग करना और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना और जहां संभव हो सके बायोडिग्रेडेबल विकल्प चुनने की आवश्यकता है। अनावश्यक बिजली की खपत भी कम करने की आवश्यकता है। एलईडी बल्ब का उपयोग एवं उपकरणों को अनप्लग करना चाहिए जब उपयोग में न हों और ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों को उपयोग करना चाहिए।

इन सभी प्रयासों से हम पर्यावरण को बचाने में सक्षम होंगे और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरित भविष्य सुनिश्चित कर सकेंगे। आइए हम सभी मिलकर इस नए साल में यह संकल्प लें कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और उसके संरक्षण के लिए कदम उठाएंगे। याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा उठाए गए छोटे-छोटे कदम भी पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

अध्यक्ष नगरपालिका परिषद देवरी को पद से वापस बुलाने निर्वाचन कार्यक्रम जारी, मतदान 19 जनवरी को

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद देवरी जिला सागर के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतदान 19 जनवरी, 2026 को होगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 29 दिसम्बर, 2025 को जारी हुई। मतदान 19 जनवरी, 2026 को होगा। मतगणना तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा 21 जनवरी को सुबह 9 बजे से की जायेगी। सिंह ने बताया है कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरपालिका परिषद देवरी के नगरीय क्षेत्र पर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है।

देवरी की जनता में चर्चा भारी है कि ऊंट किस तरफ करवट लेगा?

गौरतलब हो कि नेहा अलकेश जैन के नपा अध्यक्ष बनने से लेकर आज तक नगरपालिका देवरी विवादों में घिरी रही। सागर जिले की एक मात्र देवरी नगरपालिका जहां भाजपा मेंडेट जारी नही कर पाई थी, इस दौरान तत्कालीन भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया थे। जानकारों की माने तो यहां भाजपा इस मामले में जिले के अंदर देवरी में फिसड्डी साबित हुई थी। क्योंकि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद समन्वय न बनना। हम आपको बता दें कि देवरी नगर पालिका चुनाव के समय कुल 15 वार्डों में से 11 पार्षद भाजपा समर्पित,2 पार्षद निर्दलीय, 2 पार्षद कांग्रेस, से विजयी हुए थे। पार्षद दल के नेता न चुने जाने एवं असहमति से भाजपा दो भागों में बंट गयी। दोनों निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा में पुनः वापिसी की और दोनों निर्दलीय पार्षदों में से एक ने भाजपा समर्पित बबलू जैन सिनेमा के पक्ष में मतदान किया तो दूसरे ने भाजपा समर्पित नेहा अलकेश जैन को अपना समर्थन दिया एवं कांग्रेस समर्पित पार्षदों ने अलकेश नेहा जैन को अपना समर्थन दिया जिससे परिणाम यह हुआ कि नेहा अलकेश जैन नपा अध्यक्ष पद पर 8 मत प्राप्त कर 1 मत से विजयी हुई। वहीं प्रतिद्वंद्वी के रूप में सरिता बबलू जैन को हार का सामना करना पड़ा। कुछ महीनों तक नगर पालिका अध्यक्ष अपने कार्य को गति दी लेकिन धीरे-धीरे देवरी नगर में वार्डों के विकास कार्यों को लेकर पार्षदों और अध्यक्षता के बीच मतभेद होने लगे, जिसका परिणाम देवरी की जनता के सामने है। अब देखना यह होगा कि खाली और भरी कुर्सी के इस महाकुंभ में ऊंट किस ओर करवट लेता है?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सक्ती जिले में स्वच्छ पेयजल की मजबूत बुनियाद

(पेज 1 का शेष)

यह निवेश इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती।

हर घर जल की ओर निर्णायक कदम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन का सघन और प्रभावी क्रियान्वयन सक्ती जिले में दिखाई दे रहा है। अब तक 1 लाख 37 हजार 139 घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। जिले के 181 गांव 'हर घर जल' से प्रमाणित हो चुके हैं, जबकि जिला गठन के समय यह संख्या महज तीन थी। यह परिवर्तन प्रशासनिक प्रतिबद्धता और योजनाओं के धरातल पर उतरने का स्पष्ट प्रमाण है।

चारों विकासखंडों में समान गति

सक्ती जिले के चारों विकासखंड सक्ती, जैजैपुर, डभरा और मालखरौदा में नल-जल योजनाओं का कार्य लगभग समान गति से आगे बढ़ा है। सक्ती विकासखंड में 36 हजार 087 परिवारों में से 34 हजार 176 परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुके हैं। जैजैपुर विकासखंड में 43 हजार 448 परिवारों में से 35 हजार 400 परिवारों तक घरेलू जल कनेक्शन पहुंच चुका है। डभरा विकासखंड में 40 हजार 278 में से 33 हजार 338 परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। मालखरौदा विकासखंड में 36 हजार 432 परिवारों में से 34 हजार 225 परिवारों तक पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो चुकी है। यह संतुलित प्रगति दर्शाती है कि विकासखंडों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया और हर क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई।

221 योजनाएं पूर्ण, शेष पर तेज काम

स्वीकृत 565 योजनाओं में से अब तक 221 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ाए जाने से शेष योजनाओं को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। लंबित योजनाओं के कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए नियमित समीक्षा, फील्ड मॉनिटरिंग और विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जनभागीदारी और पंचायतों की भूमिका

सक्ती जिले में जल जीवन मिशन की सफलता का एक बड़ा कारण ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी है। जल स्रोतों के संरक्षण, पाइपलाइन बिछाने, टंकी निर्माण और योजना की निगरानी में ग्रामीणों की सहभागिता ने योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया है। इससे न केवल योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि लोगों में स्वामित्व की भावना भी विकसित हुई है।

महिलाओं और बच्चों के जीवन में बदलाव

नल से जल की उपलब्धता का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के जीवन में देखने को मिल रहा है। पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी अब काफी हद तक समाप्त हो रही है। इससे महिलाओं का समय बच रहा है, जिसे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े कार्यों में लगा पा रही हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जल जीवन मिशन को केवल लक्ष्य आधारित योजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना है। प्रशासनिक स्तर पर निरंतर समीक्षा, तकनीकी गुणवत्ता पर जोर और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने की नीति ने सक्ती जिले को एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। यह स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं, बल्कि उनके परिणाम दिखाने पर केंद्रित है।

मील का पत्थर बनता जल जीवन मिशन

सक्ती जिला आज 'हर घर जल' की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य शासन और जिला प्रशासन की सक्रियता, विभागीय समन्वय और ग्राम पंचायतों की सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। जल जीवन मिशन न केवल सक्ती जिले के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह मिशन ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदलने का सशक्त उदाहरण बन चुका है।

अन्नदाता

मध्यप्रदेश शासन

पराली न जलाएं, धरती और जीवन बचाएं

उपजाऊ शक्ति में वृद्धि | प्रदूषण से मुक्ति | अर्थव्यवस्था को गति

मिट्टी के रूप में मिले वरदान को नष्ट होने से बचाएं

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री — नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ये विकल्प अपनाएं

हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम यंत्र का उपयोग

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का उपयोग कर सीधी बोनी

रीपर से कटाई के बाद जीरो टिलेज मशीन से सीधे बोनी

बेलर मशीन का उपयोग कर धान की पराली और मक्के के तने के बेल्स बनाएं

धान की पराली का प्लेट्स, ब्रिक्स और बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में उपयोग

प्राकृतिक खेती को अपनाएं

मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों के बढ़ावे से मिट्टी की उर्वर शक्ति में वृद्धि

रासायनिक पदार्थों से मुक्त होने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से मुक्ति

प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कोई कमी नहीं

R.O. No. : D19257/25

आइये, स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए पराली न जलाने का प्रण लें....

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)